must be taken up... (Jntemtptions) Now, the country should know it. We are speaking not only before you but we are speaking before the bar of Indian public opinion. And I want to make the Indian public opinion know that we are dead honest in passing these two Bills, and it is the Government which is sabotaging the work of the Rajya Sabha,, by preventing a discussion on the tw_0 motions relating ito the families of. . . *(Interruptions)-*

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आदरणीय विरोधी दल के नेताओं ने जो बात कही हैं उसका कारण एक ही है । पिछले पन्द्रह दिन से इनको कोई ख्याल मजदूरों का नहीं आया, आज तक इनके दिल में मजदूरों के लिए कोई प्रेम उभरा नहीं । अब क्यों उभरा है ? वह सिर्फ इसलिए कि ये सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सरकार नहीं, हम गरीबों के हामी हैं । लेकिन जब आप गरीबों के हामी बनते समय यह शर्त लगा देते हैं तो कान्तिभाई का मामला आप समझते हैं कि गरीबों के ऊपर है । आप गरीबों के समर्थक नहीं हैं, केवल अड़चन डालने के आदी हैं । . . *(Interruptions).*

श्री कल्प नाथ राय : उपसभापति महोदय, कान्ति देसाई के भ्रष्टाचार पर बहस अगर मंगलवार को नहीं होगी, भूपेश गुप्ता के सवाल पर बहस नहीं होगी तो सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी . . . *(Interruptions)*

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported decision of the Organisation of Petroleum Exporting Countries to raise price °f Crude Oil and its likely repercussion on our Economy

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers to the reported decision of the Organisation of Petroleum Exporting Countries to raise price of crude oil and its likely repercussion on the economy of our country.

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): Sir, the annual consumption of petroleum products for the year 1979 is expected to be around 30.5 million tonnes of which around 4.1 million tonnes will be imported and the balance, namely, around 26.4 million tonnes will be produced by our own refineries. The total amount of crude which will be required to be imported during 1979 to supplement indigenous production of crude is expected to be 16.75 million tonnes. This quantity of crude would have cost us Rs. 14.24 crores at current prices. However, at the prices now announced by OPEC the total import bill for this crude will be Rs. 1566 crores. The cost of 4.1 million tonnes of products to be imported will be Rs. 468 crores, making a grand total of Rs. 2034 crores. This ig approximately 10 per cent higher than it would have been if there had been no price hike.

The implications of the OPEC price hike are being, carefully considered by the Government from all points of view. I would like to assure the House that whatever decisions are taken will b_e in the best interest of the national economy and that the smooth supply of petroleum products will be maintained under all circumstances. The House will appreciate that it is not possible for me *to* say anything more on thi_s subject at this stage.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं । उ होंने कहा है कि किसी प्रकार की कठिनाई पैदा नहीं होने देंगे और सरकार इस विषय में बड़ी विजिलेंट है । उन्होंने यह भी कहा है कि अब नया जो भार आएगा व ह

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

1566 करोड़ का होगा । यह भार बहुत पर्याप्त है । मैं समझता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा धक्का नहीं पहुंचेगा लेकिन एक आम आदमी की कठिनाई में बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि जहां पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी उससे पेट्रोल और केरोसीन आयल का तो कोई संबंध नहीं है लेकिन इससे जो दूसरी चीज बनती हैं सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक की चीजें आदि, उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा । मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा यदि वह दे सकने की स्थिति में हों तो क्या दूसरे जो बाई-प्रोडक्ट्स पेट्रोल से संबंधित हैं उनकी कीमतें तो नहीं बढ़ाई जायेंगी ? जो कीमतें बढ़ती हैं वह 14.5 परसेंट के हिसाब से बढ़ी हैं । यह भी देखने में आया है कि देश-विदेश में इसकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं । अमेरिका ने इसका घोर विरोध किया है । रूस की ओर से इसका स्वागत किया गया है । मुझे संदेह है कि ये जो पट्रो-डालर्स हैं व कोल्ड-वार के भाग तो नहीं बन जायेंगे ? कोल्डवार जो अभी-अभी समाप्त हुआ है अब किसी प्रकार से दुबारा तो नहीं खड़ा हो जाएगा ? हमारे देश की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? अभी रुपये की कीमत को बदला गया है । मैं पुछना चाहता हूं, यह ठीक है आपके अधीन नहीं है लेकिन यदि आप कुछ प्रकाश डाल सकें तो बताने की कृपा करें कि जो रुपये की कीमत बदली गई है क्या यह जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है इससे तो नहीं बदली गई है ? 1978 जून में, जो ओपेक देश है उनकी एक कमेटी की बैठक हुई थी । मुझे याद है इससे पहले 1973 में यह ओपेक आर्गेनाइजेशन बना था । उस समय और इसके पश्चात् बराबर वे कीमतें बढ़ाने के संबंध में चर्चा करते रहे । जून 78 में जो बैठक हुई उसमें उन्होंने प्राइस फ्रीज करने की बात कही थी । जब प्राइस फ्रीज करने की बात हो रही थी उसके साथ-साथ अन्य नेताओं ने बढ़ाने की बात भी कही थी । तब यह लगता था 6 महीने पहले कि मिडल ईस्ट कंटरीज तेल की कीमतें बढ़ा सकते हैं । मंत्री महोदय यह प्रकाश डालने की कृपा करें कि इन 6 महीनों में प्राइस को बढ़ने से रोका जाएगा या नहीं और अगर नहीं रुकती तो हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं ? यह भी कहना है कि जो इन्टरनल इनफ्लेशन है उसके कारण से जो उनकी आमदनी होती है वह आमदनी न के बराबर रह गई है । ये दो देश हैं इन दो देशों को छोड़ कर अमेरिका के जो वक्त के साथी हैं उनके नेताओं ने इसका विरोध किया था । शेख अमीन जो साउथ अरब के हैं उन्होंने समर्थन किया । यह भी कहा कि प्राइस हाइक न की जाए । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्टरनल इनफ्लेशन के आधार पर उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं ? उन्होंने यह कहीं नहीं बताया कि 45 परसेंट कीमतें बढ़ाने का उन्होंने आधार क्या लिया है । यदि सरकार को इसकी जानकारी है कि उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तो उसका आधार क्या है और उसका संबंध, जो प्राइस इनफ्लेशन है उससे कितना है, तो यह जरा साफ बताने की कृपा करें ।

दूसरे हमारी रिफाइनरीज में जो क्रूड रहता है सामान्यतः पद्धति हमारे देश में यह है कि तीन हफ्ते का क्रूड रहता है लेकिन दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके यहां साम न्यतः 90 दिन का रहता है । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं ?

मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक तो दूसरे देश हैं जैसे रूस है, मेक्सिको है । मैक्सिको ने डिक्लेयर किया है कि वह 10-12 परसेंट बढ़ोतरी करना चाहता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनसे हम इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं । इंडोनेशिया में तेल के बहुत से स्थान हैं । वहां तेल मिलेगा । मैं सुझाव देना चाहता

हूं कि हम इंडोनेशिया के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर सकते हैं। हम उनके यहां अपनी नो हाउ दें और तेल निकालें। जब दो-चार साल में हमारा काम पूरा हो जाएगा 1 P.M. तब हम तेल उपलब्ध कर सकेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश से आइरन-ओर, शुगर और चाय का एक्सपोर्ट होता है। काफी बड़े पैमाने पर हम इन चीजों का विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं। जिस प्रकार से तेल पैदा करने वाले मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज अपने तेल की कीमत बढ़ा लेते हैं, क्या उसी प्रकार से हम भी आइरन-ओर, चाय या शुगर आदि का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के साथ मिलकर कोई ऐसा संगठन बना सकते हैं जिससे हम भी तेल पैदा करने वाले देशों की तरह इन चीजों की कीमत घटा या बढ़ा सकें और दुनिया के बाजार में दृढ़ता-पूर्वक खड़े हो सकें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आखिरी सुझाव दिया है उस के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आइरन-ओर तेल का कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज दुनिया में बहुत पैदा होती है और दूसरी चीज की बहुत कमी है। दोनों का कोई संबंध नहीं बन सकता है। लेकिन उनकी अपनी राय है और उनका सुझाव गवर्नमेन्ट के लिए है। जहां तक ओपेक कन्ट्रीज द्वारा तेल की कीमत बढ़ाने का संबंध है, उनका कहना है कि दुनिया में जिस तरह से कीमत बढ़ रही हैं और जिस तरह से डालर की कीमत घट रही है उसकी वजह से उनको जो चीजें विदेशों से खरीदनी पड़ती हैं वे बहुत मंहगी पड़ रही हैं। आप जानते हैं कि अरब देश लगभग सभी चीजें बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं। उनका कहना है कि वे इसी वजह से तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। यह बात सच है कि पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था उस वक्त हमारे विदेश मंत्री और दूसरे लोग वहां गये थे और उन्होंने उनको यह बात समझाने की कोशिश की थी कि तेल की कीमत बढ़ाने से डवलपिंग नेशन्स को हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा लगत है कि हमारी कोई बात नहीं चली है औरा हम तेल की कीमत स्थिर रखने में कामयाब नहीं हो पाये हैं।

जहां तक हमारी रिफाइनरीज में तेल के स्टोरेज का सवाल है, यह बात सच है कि हमारे पास तीन हफ्ते तक तेल की स्टोरेज की क्षमता है। इसको और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, यह एक अच्छा सुझाव है जिस पर हमारे यहां विचार चल रहा है। जहां तक दूसरे देशों से तेल मंगाने का संबंध है, हम रूस से तो तेल मंगाते ही हैं, अन्य देशों खास कर इंडोनेशिया के साथ इस संबंध में हमारी बातचीत चल रही है। हम देख रहे हैं कि क्या हम वहां से तेल ले सकते हैं या नहीं। जहां तक इंडोनेशिया को हमारे नो-हाऊ देने की बात है, इंडोनेशिया में दूसरे मुल्कों के के लोग काम कर रहे हैं। वहां से तेल प्राप्त करने के संबंध में बातचीत हो सकती है। हमारी यह पूरी आशा है कि तेल की कीमत बढ़ने से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर जो कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है उससे बचने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तेल की कीमत बढ़ने से फर्टिलाइजर की कीमत पर भी असर पड़ेगा और जो पैट्रो-केमिकल्स हैं उन पर भी असर पड़ेगा। इनके अलावा अन्य दूसरी चीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस संबंध में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। हमारी अर्थ-व्यवस्था का इस तेल की कीमत की बढ़ोतरी से कोई कुप्रभाव या विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम आवश्यक कदम जरूर उठाएंगे।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, the hon. Minister has given replies to various points and I do not want to take much of his time because he seems to be in a little hurry. I would only seek a few clarifications from him. Sir, actually what he has replied to my

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

hon. colleague, Mr. Mathur, namely the imports, know-how, devaluation of Dollar, etc. are only the short-term problems. And I can understand that. Sir, in this country, we appointed two committees, one in the 1950s called, the Energy Committee, and then the Fuel Policy Committee in 1970. This Fuel Policy Committee has evolved a rational policy for this country to be followed on a long-term basis. Sir, I am coming to the conclusion that with the euphoria of more foreign exchange coming to the coffers of the Government, the Government is on a spree of importing many things which really amounts to a laxity cf creating an atmosphere of credit-based imports, just like the one made under PL 480 by our great friend, Mr. S. K. Patil, who was a Minister here and who showed that the food was surplus. Therefore, I would like to tell you, I would like to warn you and your Government that the credit-based import is not a long-term solution to the problem. The Fuel Policy Committee has really evolved certain principles for strengthening this country's economic base. In this connection, Sir, I would request you that a radical restructuring of the energy base of the economy has to be attempted and the regulation of consumption has also to be attempted. For this purpose I do suggest to you that a little tightening of the belt for some persons, for some people, who are the elite, who consume more in this country as against the poverty-stricken people, that type of restructuring in the economy is necessary. Only you yourself saying that this also is under consideration won't solve the problem. We see at present that the conditions have been a little bit liberalised because of the false notion of credit availability. In this connection I do not want to bring in any other economic issues because you yourself are a very clever and intelligent person.

यदि हिन्दी में कहें तो आप बहुत काबिल आदमी हैं, आप सब समझते हैं ।

I only want to know what my friend says about the synthetics etc., namely, that even if it costs more it is consumed by only ten per cent f*id we do not care. Very recently your Government has introduced a surcharge of ten per cent on production of cloth to support the standard cloth scheme, which is being used by the poor people. Similarly, for fertiliser and for light diesel oil, which is being used by the tractor owners, particularly the farming community, whereon our entire food base depends, and the taxi drivers and scooterwallas, I would request you to prescribe a similar type of surcharge to meet this extra cost; say the difference between Rs. 1500 crores and Rs. 1,000 crores has to be met from the corporate sector, the elitist population of this country. *(Time bell rings).* For that purpose you should say that the fertiliser and the farmer will remain mostly untouched. You cannot commit it just now. But the base should be changed and a radical restructuring should be made in the consumption econ'omics whereby a long-term solution can be found.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Sir, I am grateful to the hon. Member for his suggestions. We will certainly keep them in mind while deciding our future course of action.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Very good. I have done your job.

SHRi PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the hon. Minister has mentioned that the import bill for the full year taking petrol and crude into consideration will mean another Rs. 468 crores, if I have correctly heard his figure. Naturally he may take note of the other suggestions but they too will have economic implications, like enhancing the storage capacity will mean blocking your capital and money. I do not know in the present financial situation to what extent he would be in a position to do it. But if these Rs. 468 crores are completely

passed on t_0 the consumer, it will have its effect on the price front. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether he has had any discussion with his colleague in the Finance Ministry for restructuring the excise duty because a considerable part of our revenue comes from excise duty on petroleum products. Therefore the question is whether he is in a position to absorb this additional burden by restructuring the excise duty without passing it on to th_e consumer. Secondly, Sir, has our representative failed in the Paris Conference mainly for the reason that somehow we have not yet been able to establish a rapport among the various developing nations as to how to utilise the raw material resources to the optimum advantage of the various developing countries? And whatever resources we have, we are trying to depend on them, and perhaps rightly, but in that process the developing nations in the ultimate analysis are hard hit. Therefore, instead of having the global approach and attitude, whether we can emphasise more and more on bilateralism not only to our mutual advantage but at the same time to explore the possibilities of depending upon our resources and getting the maximum advantage out of that situation, because I do not know how much time it will take to compensate our deficiency in this particular area. Until and unless we are in a position to develop the alternative energy policy —and it is not easy to do it overnight—it will not be possible to solve this problem. Certain exercises are being made in this direction since the oil crisis in 1973, and the exercise is going on. But it will take time. Therefore, in between, an interim arrangement has to be there. I understand it but I would not like to disclose it; the Minister also knows it that we were in a position to enter into some sort of agreement with the various development funds Jn the Gulf countries. Whether he would lay more emphasis on it so that both the countries, particularly the countries of the developing group, are benefited by it.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Sir, I am grateful to hon. Pranab Mukherjee for giving us some advice on how to go at the absorption of this price hike. I can assure him that it will be our best endeavour to see that the economy is not hurt and the common man to the extent possible is not loaded with the additional responsibility. But how will it happen really and what may happen is very difficult to say immediately. It will take us some time before we can come to a conclusion.

So far as his emphasis and his broad hint at bilateral efforts between the developing nations, especially the OPEC countries and India are concerned, I am one with him in the stand that we should try our best to build a rapport with them and also see what they can do to help us out of this particular situation in terms of, say for example, helping us in our developmental expenditure by giving us soft loans and so on. I am not sure whether we will succeed but we have been toying—even the previous Government was successful tc some extent—with these ideas and the result of it has really been not very unfavourable. But this is a general policy of the OPEC countries that whereas in the matter of price, they will treat the developing and the developed nations in one and the same way, they do offer sometime soft credits tg strike off the load that accrues to the developing nations. And that effort will continue.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, यह तेल जो है यह अन्तर्राष्ट्रीय नीति का बहुत बड़ा सवाल है । अब ओपेक कंट्रीज ने कीमत बढ़ा दी है इसलिए हम लोगों को परेशानी भगतनी पड़ेगी और हमारे पेट्रोलियम मंत्री भी काफी परेशान हैं कि इसकी वजह से हमारे देश में महंगाई न बढ़े और हमको उचित मात्रा में तेल भी मिलता रहे। तो इसके लिए

[श्री योगन्द्र शर्मा]

पहली जरूरत जो है वह यह है कि अब आप अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति को ठीक रखें। वह यदि आप नहीं रखेंगे तो आप मारे जाएंगे। पहली आवश्यकता यह है कि हमारे पास समय भी नहीं है, शायद विषय भी नहीं है लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आप अन्तर्राष्ट्रीय नीति में गड़बड़ा रहे हैं और डगमगा रहे हैं। इसलिए यह मार आपको लगी और पूरे देश को यह मार खानी पड़ रही है। आपको बहुत ही अच्छी सलाह दी गई है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं यह ऐसे कंट्रीज हैं जो काफी मात्रा में तेल पैदा करते हैं, मसलन सोवियत यूनियन, जहां तक मेरी जानकारी है कि दुनिया में सब से अधिक क्रूड आयल यहां पैदा होता है। यदि हमारी गलत सूचना होगी तो मंत्री महोदय हमें दुरुस्त करेंगे लेकिन हमारी सूचना यही है। तो आपके द्विपक्षीय संबंध जो हैं इनको मजबूत करना चाहिए ताकि आपको अधिक तेल मिले और कीमत भी कम देनी पड़े। हम जहां तक जानते हैं ओपेक कंट्रीज ने यह अपनी नीति घोषित की है कि विकासशील देशों के साथ वे कुछ दूसरी नीति बरतेंगे, अनेकों रूपों में बरतेंगे, एक रूप की बात तो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद की और दूसरा साफ्ट लोन वगैरह देंगे। तो एक रूप में ले लेना चाहिए। हम समझते हैं कि इस संबंध में क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, यह हम नहीं जानते हैं मगर हमें विश्वास है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर इस संबंध में आवश्यक कदम उठायेंगे और द्विपक्षीय वार्ता के जरिये जो भी मार लग रही है, उसका प्रतिकार करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में जब जब तेल की कीमत बढ़ी है, हाय तोबा मची है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मची है इसलिए हम चाहने लगे हैं कि कोई दूसरा भी तेल का अल्टरनेटिव, विकल्प, हमको खोजना चाहिए या नहीं खोजना चाहिए। हम समझते हैं कि दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं, हमारे देश में भी कई वर्ष पहले, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फ्यूल इंस्टीट्यूट धनबाद में है उसने कोयले से तेल निकालने की खोज कर डाली थी, हमारे यहां पर कोयले का काफी भंडार है। लेकिन हम तो नकल करते हैं, अमरीका की करते हैं, एफ्लुएंट देशों की नकल करते हैं, अपने साधनों के मुताबिक नीति नहीं चलाते हैं, हम यदि कोयले से तेल निकालने की कोशिश करें और करते होते, जिसमें ब्रेक थ्रू किया था हमारे धनबाद के फ्यूल इंस्टीटयूट ने तो हम समझते हैं शायद आज हमको तेल के लिए इतनी कीमत नहीं चुकानी पड़ती जितनी हमको आज चुकानी पड़ रही है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि कोयले से तेल निकालने के सिलसिले में क्या स्थिति है ?

इस सिलसिले में हम कहना चाहते हैं कि हमारा देश गर्म मुल्क है, इतनी गर्मी पड़ती है कि खून भी काला हो जाता है। दूसरे देशों में सोलर एनर्जी फरनिश की जा रही है। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से सीधा इसका ताल्लुक नहीं है लेकिन तेल एक एनर्जी का प्रधान तत्व होने के नाते हमको पूरी एक एनर्जी पालिसी इवाल्व करनी पड़ेगी। यहां एनर्जी मिनिस्टर कोई है, कोयला मिनिस्टर कोई है, पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई है, पता नहीं इनमें तालमेल होता है या नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं इस बात को देखते हुए कि ओपेक कन्ट्रीज के डालर के मूल्य में अवमूल्यन होने के कारण अपनी कीमतें बढ़ायीं और अपनी कीमतें बढ़ायीं विकास शील देशों के सम्वेदन के उस फैसले के अनुसार कि उनको कच्चे माल की उचित कीमत मिलनी चाहिए तो जो उन्होंने कीमत बढ़ायी है उसको सामने रख कर के हम अपने देश में एक ऐसी सुनियोजित समन्वित एनर्जी पालिसी बनायें ताकि हमको बाहर से तेल कम लेना पड़े और अपने साधनों से तेल बनाने में या दूसरी पावर तैयार करने में ज्यादा सहूलियत हो और साथ साथ

हम यह भी आश्वासन चाहेंगे कि, कैसे करेंगे इस माने में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब काफी कुशल आदमी हैं इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, माननीय योगेन्द्र शर्मा जी ने जो बात कही है दुर्भाग्यवश मैं उससे सहमत नहीं हूं । क्योंकि उनसे असहमति करने को दुर्भाग्य मानता हूं इसलिए मैंने दुर्भाग्यवश कहा है । यह बाइलेटरल रिलेशंस की कमी नहीं है । ग्रुप आफ 77 डेवलपिंग कन्ट्रीज में नार्थ साउथ डाइलाग के वक्त उसके आगे पीछे बातचीत हुई थी, हमने ही नहीं बल्कि सबने कहा ओपेक कन्ट्रीज को कि दाम मत बढ़ाओ, ओपेक कन्ट्रीज के दाम बढ़ाने में सब विकासशील देश शामिल नहीं हैं । विकासशील देश ओपेक कन्ट्रीज को छोड़ कर नहीं चाहते थे कि दाम बढ़े । लेकिन तेल का दाम डालर से जुड़ा हुआ है । डालर का अवमूल्यन हुआ है और यह कण्ट्रीज कहते हैं कि हम साबुन से लेकर, सिग्रेट से लेकर सब चीज बाहर से मंगाते हैं, हमारी मंहगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और डालर का अवमूल्यन होने से हमारा जो बजट में घाटा है बहुत बढ़ रहा है । इसलिये हम दाम बढ़ाते हैं । तो मैं उनका डिफैन्स तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं तो हम रोक नहीं सकते । वे भी स्वतंत्र देश है, चेष्टा बहुत हुई ।

दूसरी बात, एक गलतफहमी इसमें यह है कि कोई हमारी परराष्ट्र की नीति के कारण इसमें गड़बड़ हुई है । न तो इसके कारण गड़बड़ हुई है और न ही कोई इसमें तबदीली हुई है जिसके कारण यह कहा जा सके । चर्चा बाहर भी है और लोग कहते हैं, पर मैं माननीय शर्मा जी से यह प्रार्थना करूंगा सबसटांस को देखें और बातों में अगर न जाएं तो कोई परिवर्तन नहीं लगेगा और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश की जो नान-अलाइंड व्यवस्था है, जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी शन्ति के सम्बन्ध में नीति है, अगर.....

(*Interruptions*)

श्री योगेन्द्र शर्मा : यानी आप नान-अलाइंड को यह चाहते हैं कि अलाइनमेंट टु एवरीबाडी । आपने नान-अलाइनमेंट का तत्व खत्म कर दिया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं । हम अगर सब के साथ सहमत होते तो जिम्बाबवे में जो स्ट्रगल चल रहा है और उसकी मारफत से और उस रोडेशिया के शासकों के विपरीत सब तरह की सहायता देने का वचन नहीं देते जाम्बिया के प्रधान मंत्री को ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : बहुगुणा जी आप परराष्ट्र मंत्री नहीं हैं पर यह परराष्ट्र मंत्री के शब्द हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बरहाल हम सब के साथ अलाइण्ड नहीं हैं । जिस दिन ऐसा होगा उस दिन बहुत सारे लोग, इस तरह से रहना उनके लिये नामुमकिन हो जायगा । यह सम्भव नहीं है और योगेन्द्र शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि यह बात सच नहीं है । तीसरी बात उन्होंने कही कि कोयले का इंस्टिट्यूट, धनबाद ने जो तेल का तरीका निकाला था, इस बात को अमरीका और रूस वाले भी देख रहे हैं। यह बहुत महंगा सौदा है । कोयले से तेल बनाना तेल को बाहर से मंगवाने से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा । लेकिन एनर्जी पालिसी में एटामिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विण्ड एनर्जी, जियो-थर्मल एनर्जी, सब प्रकार की खोज की जा रही है, काम पुरे जोर से हो रहा है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या कोई फार्मूलेटिड एनर्जी पालिसी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हां ।

एक माननीय सदस्य : आपके हाथों से.

(Interruptions)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपके ऐसे गोरे आदमी के हाथों पर ज्यादा जल्दी दिखेगा । हम तो काले हैं, थोड़ा देर से दिखेगा । अब मान्यवर, उन्होंने एक बात और कही थी । माननीय शर्मा जी ने कहा था कि खाद का दाम बढ़ना नहीं चाहिये । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारी तो कोशिश पिछले सालों से हो रही है कि दाम न बढ़े ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हमने फर्टिलाइजर के बारे में कहा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : लेकिन इसको देखना पड़ेगा । हम कुल जमा-जोड़ करके देखेंगे कि किस तरह बढ़ते हुए दाम को इकानमी में एवजाबं करें । इसका एकाएक एलान करना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I have to bring three points to the attention of the hon. Minister, Firstly, I agree with, I think, hon. Member Yogendraji's point that at least the additional out-go on crude should not simply be added to the very heavy looming deficit that we are going to have in our balance of trade. It is being forecast. Therefore, this year our deficit wiH be about Rs. 1000 crores and the deficit from crude should not be added to that. If that is done I do not know whether our economy can stand this. That is one point to which I call the attention of the hon. Minister. The second thing to which I call the attention of the Minister is what has been referred to by others also, namely, that we should now look to our own resources. For that I commend what is being done by this Ministry and by the ONGC for intensifying off-shore and on-shore oil production. I think" that we should push this to the maximum that we can, not paying too much attention to the scare that is being raised about depletion.

Secondly, I think the economy in the use of fuel which was going forward well till about a year ago—that is, replacement of coal in .place of fuel oil, replacement of fuel oil in place of HSD, replacement of HSD in place of petroleum—seems to have—at least ia my State of Timil Nadu—become some what slow in the last 12 months. The need for economy in the use of crude should be looked into by the Minister and pushed forward, as we were doing till about a year ago. Ia this connection I would call the attention of the Minister to the fact that the most wasteful use of crude is in regard to automobiles. The conver. sion co-efficient of using petroleum in the automobiles is something like 5 to 20 per cent, which is the lowest in this country and I think that anything that can be done to save on the use of petrol in our automobilies should be looked into.

Thirdly, I would say to the Minister that in addition to what has been said about the other sources of fossil oil, I think the use of bio-fuel which abounds in our rural countryside—namely, forests and forest products, grasses, leaves as well as cow-dung and so on—should be further pushed forward. I do not know whether it comes under his Ministry or not. This is called bio-fuel.

My last comment is to call the attention of the Minister to the fact that this is only a tip of the iceberg. There is going to be a long-term affect. The oil prices and energy prices are going to go on rising. The period of low energy prices is over now. And, therefore, his Ministry and our Government—th° present and future Governments—must be ready now for facing a regime of increasing oil prices. Here I want to say that all calculations made by the scientists, geologists show that at the present rate at which it is being used, our fossil fuel will be exhausted by the

middle of th$_e$ twentieth century. This is not due to us. Ninety-nine per cent of our annual production of 7 billion tonnes of coal equivalent is consumed by the industrialised countries and we and others of the developing countries consume only l per cent. And, therefore, I think that th$_e$ regime of higher energy prices is a regime with which our Government, our Minister and the Ministeries of the Government and the people have to live in the future. Moreover, I call attention to the point made by Mr. Mukerjee. I think that many of us don't know this. I said this at the time when the first OPEC oil Price hike took place. I think, perhaps, the Minister knows this. At that time I was in Europe and I found that in Europe, one barrel of oil was being sold for 10.739 dollars of which the European countries, which had done nothing to produce that oil, were obtaining 5.1 dollars and the countries which produced the oil, the Middle East countries, were getting only 0.853 dollars. This was the situation which led to their raising the prices. I think, therefore, this suggestion to *see* whether on this ground we can absorb some of the increases should be looked into by the Minister. I think, for instance, that at the time the OPEC raised the price, there need not have been the need for it if in Asia or Europe the non-producing consuming countries had agreed to decrease their share per barrel of oil by 50 per cent, from six times that of the producer countries to 3 times.

Finally, I would say to the Minister that my own prediction as an economist is that we are going to go in for a period of rising oil pries, rising fossil oil and energy prices, that the increase that has *now* been decided by the OPEC countries, let u$_s$ remember, is because of the world inflation that has annualised now at 15 per cent and has actually reduced the real price to 5 dollars and in another three years it will be back to 3 dollars if the present rate of inflation continues. And what is being put out by the Western countries that the world inflation is due to OPEC oil prices is a canard. Th$_e$ Minister knows that it is not so. It is due to increased, supply of money in each country, increased deficit financing and various inflationary factors.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Sir I agree with the premise developed by the hon. Member in regard to the inflationary pressures the world is facing in its economy as a whole. So far as the fossil fields are concerned, as far as oil is concerned, the situation is not as alarming as it used to be looked upon by many futurologists in thi$_3$ particular sector. Just recently, Sir, Mexico-has found an oil field as big as Saudi Arabian oil fields which are the biggest in the world today. Similarly, the Alaska field has come, the North Sea field has come and there has been a great deal of oil found out by the Chinese both on land and the sea between Taiwan and Japan, between North Korea, South Korea and Japan, between South Korea, North Korea and China. All sea base is supposed, from all calculations, to be full of oil. So the large amount of fear expressed on the ground that oil is only available in the Middle East or in some areas of the U.S.S.R, or in some areas of the U.S.A. and in small amount Mexico is all going wrong and more and more oil is being found out.

I am sure that by the time of the turn of the century energy of various types, solar energy, wind energy, geothermal energy, all forms of energy would really have come in the grips of human race and, perhaps, then the whole concept of energy pricing etc. will have its own future. Nevertheless, what really is needed is to give a great deal of attention to all that technology, all that type of research and that type of hunt for oil in the country alongside with developing these new sources of energy.

The hon. Member is quite right about 'biogas fuel energy. We have been giving a great deal of attention

[Shri H. N. Bahuguna]

ta that. It is true that the distribution of work in the country has not been in the sense that the Energy Ministry is bifurcated in this country for long now. In fact, the Janata Government haa been really a continuation at least in this: there has been a total continuation of what was being done in the past for right or wrong. I am neither approving nor disapproving the situation. But the energy base ia now being looked after by tlie Ministry—in the Atomic Energy by the Prime Minister's Secretariat as was being done earlier. Solar energy and similar other types of energies are being looked after by different types of bodies.

As far as the hon. Member's suggestion about the total outgo of this particular amount on crude and petroleum product is concerned, it cannot be just taken on the deficit budget of the Government. I think it is a realistic assessment of the situation but how to improve the situation is something which is still under our consideration.

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार क्या ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम बना रही है क्योंकि तेल का और देश की सार्वभौमिकता का, आजादी का एक रिश्ता है, गंगा को भागीरथ भागीरथ प्रयास करने के बाद ही धरती पर ला पाये थे, इस मुल्क के कल्याण के लिये जो व्यक्ति या जो सरकार तेल के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करेगी वही उस का भागीरथ प्रयत्न माना जायगा और वह सरकार भागीरथ प्रयास वाली सरकार मानी जायगी । तो मैं बहुगुणा से क्या यह जान सकता हूं कि वह तेल के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये हैवी इन्वेस्टमेंट और चतुर्दिक प्रयास की कोई घोषणा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, मैं इस से सहमत हूं कि तेल के क्षेत्र में हम को अधिक से अधिक पैसा लगाना चाहिए । हम कर भी रहे हैं, जैसा कि मैंने इस हाउस में कुछ दिन पहले बताया था कि इस वक्त हमारे जो जियोलोजिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और टेक्नीशियन हैं, और जो दूसरा स्टाफ है वह सारा लगा हुआ है, जितना हमारा इक्विपमेंट है वह लगा हुआ है, उसे हम पूरा लगा रहे हैं और देश में बना भी रहे हैं और उसे बढ़ाने का इरादा है । और मेरा पूरा विश्वास है कि इस देश में जहां तक तेल का मामला है, आने वाले दो तीन साल के अन्दर हमें नये तेल के बड़े इलाके मिलेंगे । वैसे भाग्य की बात मैं इसको मानता हूं । थोड़ा भाग्य तो इसमें रहा है । पार साल हमको ५ लाख टन तेल का भंडार मिला था । इस साल हमको गैस भी मिली है जिसमें करीब दो लाख २० हजार टन बम्बई के करीब मिला है । कुछ नार्थ गुजरात में हम को मिला है । इधर जब से मैं इसमें आया हूं तभीसे इसमें हमारा प्रयत्न रहा है । तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस पृष्ठ-भूमि में हमको यह कार्य करना चाहिए था, इसके लिए जो दिशा जवाहरलाल नेहरू ने दी थी उसी दिशा के मातहत आज भी इस कार्य में दिशा दी जा रही है ।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) श्रीमन् तेल मंत्रियों ने फैसला किया कि क्रुत आयल के लिए दाम बढ़ाने का और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इसका असर भारत की अर्थ व्यवस्था पर न होने पाये । मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय बाहर के तत्वों का डटकर मुकाबला करेंगे और देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई असर नहीं होने देंगे । लेकिन हमारे यहां अन्दरूनी तत्व हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो अन्दरूनी तत्व हैं, जो आर्टिफिशियल स्केयरसिटी पैदा करते हैं, होडिग करके, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इसके लिये कोई डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रिम-अप करेंगे ? आज आपकी क्या योजना है ? आप बाहरी तत्वों का मुकाबला करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं लेकिन अन्दर के ऐलिमेंट्स के

लिए क्या कर रहे हैं यह मेरा पहला सवाल है ।

दूसरा और आखिरी सवाल यह है कि अभी आपने कहा कि हमको तेल के भंडार मिले हैं या मिलने वाले हैं...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उम्मीद है ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के चप्पे चप्पे का क्या आपने सर्वे कराया है ? यदि नहीं कराया तो क्यों नहीं ? जहां तक ले-मैन कहिये या सोशल वर्कर कहिये, हम लोगों का पूरा विश्वास है कि भारत का चप्पा चप्पा यदि आप सर्वे मुस्तैदी से करा लेंगे तो भारत की जमीन के अन्दर पर्याप्त तेल है और आखीर में आपको तेल के मामले में सफलता मिलेगी जिस तरह से जमशेद जी नौशेरजी को छोटा नागपुर में आयरन ओर मिला था ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो तेल मिलने की शुभ-कामनायें प्रकट की हैं उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जियोलाजिकल और प्रागनोस्टिक स्टडीज कर ली गई हैं । हमारे स्ट्रक्चर बेसिन कैसे कैसे है यह भी नोटिस में लाया गया है । पूरी ताकत के साथ हम यह काम कर रहे है जमीन के भीतर भी और समुद्र के भीतर भी जहां तक हम पहुंच सकते हैं । इसीलिए हमने कहा कि हमें जो कुछ मिला है या अभी तक जो जानकरी है उसमें तेल मिलने की संभावना है ।

जहां तक उनका यह सवाल था कि अन्दरूनी तत्व जो गड़बड़ करते हैं, उनका क्या किया जाए, इसके लिए राज्य सरकारों को पूरी शक्ति है और इसमें हमारा सहयोग है । केन्द्रीय सरकार सीधे सीधे इसमें कुछ नहीं कर सकती । हम उनके साथ सहयोग करते हैं, मेरा बराबर उनके साथ सम्पर्क बना हुआ है । मुझे आशा है कि ब्लैक मार्केटियर्स समाप्त किये जा सकेंगे । मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यह भी सच है कि बहुत दिनों से यह कहा जा रहा है, जवाहरलाल जी ने भी स्वराज्य के बाद कहा था कि काला बाजार करने वालों को नीम के पेड़ पर लटका देना चाहिए, लेकिन स्वराज्य के बाद वह बढ़ता ही चला गया । इसमें सख्त सजा देने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को कानून बनाना होगा और मुझे आशा है कि माननीय झा जैसे सतर्क सदस्य के चलते हमारे ऊपर जो दायित्व है, केन्द्र में और सूबों में भी, वहां हम ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ सख्त सजा देने की व्यवस्था भी करेंगे और सजा भी देंगे ।

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi): Sir, I have to ask only one question from the Hon. Minister. He is such a sophisticated Minister and the people insist on more crude, both are very contradictory.

Now, Sir, one thing I would like to ask. He is doing everything possible to let a favourable price fo$_r$ import. What is he doing about reducing the excise duty which has been increased tremendously during the last five, six years? Will the Minister or the Ministry consider giving some relief in the excise duty particularly to the essential services like transport, tractors and allied industries? They are very essential and a sort of a drawback of duty can be allowed on them when we are allowing drawback of duty to the embassy cars which draw gallons and gallons of petrol everyday at a cheap price.

I want to say another thing regarding substitute. I know the coal trade is very difficult *$W* ^T# fT^lT# f 3W. But the hon. Minister, I hope, will try to make experiments on power

[Shri Khurshed Alam Khan}

alcohol because power alcohol has been used in the past successfully, and, surely, if some research work is done, power alcohol can be found to be more useful for our transport purposes in this country.

SHRI H. N. BAHUGUNA; Sir, I am happy that the hon. Member has raised a very relevant point. We have already constituted a group to examine the pros and cons, the methodology and other type of arrangements which are necessary to make use of power alcohol for propelsion. That is already being gone into, and I hope, some results will come, I agree with him that in view of the large amount of molasses and power alcohol that we have in the country and the large amount of sugar that we produce, something of that type should be done, and that group is already at it, and I hope some results will accrue.

So far as the question of getting cheaper crude is concerned, I want to make it clear that it is not nossible for us to get cheaper crude from anywhere. In fact, I am not negotiating with anybody on it. It is not negotiable. I want, to make it clear that I am not negotiating on it with anybody lest an impression may go in the world about our friends who are giving us crude, because among the OPEC countries there is an understanding that no country will sell its crude at less than the OPEC price, otherwise they will get blacklisted.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: There is no difficulty in giving drawback of the excise duty.

SHRI H. N. BAHUGUNA-. I want to correct that position so that I do not face international complications with regard to those countries which are helping us to get crude from them ia a size much larger than they were doing previously in view of the Iranian difficulty which is staring us in the face.

So far as the question of the excise duty and other things are concerned, all of them are germane to the question relating to absorption of price hike and they will certainly have to be gone into.

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही सवा तीन बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at forty-two minutea past one of the clock.

THe House reassembled after lunch at nineteen minutes past three of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

REFERENCE TO THE STATEMENT MADE IN LOK SABHA BY SHRI CHARAN SrNGH, FORMER HOME MINISTER

SHRI BHUPESIH GUPTA (West Bengal): Sir, . . .

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) उपसभापति महोदय, चौधरी चरण सिंह ने प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के पुत्र कांति देसाई के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं ;

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I thought we had finished it in the morning.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA (Andhra Pradesh): In view of this statement. Sir, an inquiry commission is necessary. This is the opinion of the former Home Minister. Can I read out?

(Interruptions)

श्री कल्प नाथ राय : श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह के स्टेटमेन्ट के बाद यह जरूरी हो गया है कि जो प्रस्ताव श्री भूपेश गुप्त और. . .

(Interruptions)